Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 1, Jan-Feb – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 12/02/2020 Accepted on : 26/02/2020 Publication Date: 28/02/2020

Hkkjr esa f'k{kd f'k{kk% ,d ,frgkfld ifjçs{;

अश्वनी कुमार
शोधकर्ता (शिक्षा विभाग)
सत्यभामा विश्वविद्यालय परिसर तमिलनाडु ।
Email – ashwanijcmst@gmail.com

सारांश : यह सर्वविदित है कि सीखने की उपलब्धि की गुणवत्ता और सीमा मुख्य रूप से शिक्षक क्षमता, संवेदनशीलता और शिक्षक प्रेरणा द्वारा निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षक शिक्षा को पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा स्तर तक पढ़ाने के लिए व्यक्तियों के शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया है। समुदाय अपनी परंपराओं और सम्मेलनों के संरक्षण, प्रगति और संवर्धन के लिए स्कूलों की स्थापना करता है। कुशल और वास्तव में सक्षम शिक्षकों के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम बहुत जरूरी है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्राचीन शिक्षा प्रणाली और भारतीय समाज की वैश्विक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा लेने की वर्तमान प्रणाली तक ढालना शुरू करता है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 जोर देती हैः "शिक्षक की स्थिति समाज के सामाजिक–सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती हैय यह कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। शिक्षा आयोग (1964–66) ने मानाय ''भारत की नियति अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रही है'' इस प्रकार यह पेपर शुरू से ही शिक्षक शिक्षा के ऐतिहासिक पहलुओं पर केंद्रित है।

संकेत शब्दः शिक्षक शिक्षा, ऐतिहासिक, परंपराएं, संवर्धन, कार्यक्रम ।

१ परिचय :

शिक्षण दुनिया में सबसे पुराना और सबसे सम्मानित व्यवसायों में से एक है। भविष्य के नागरिकों को आकार देने का महान कार्य शिक्षकों के हाथों में सौंपा गया है। इस कार्य की प्रकृति समाज की अपेक्षाओं से निर्धारित होती है। प्राचीन भारत में, शिक्षक लौकिक के साथ–साथ आध्यात्मिक ज्ञान में भी पारंगत था, और शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी को सांसारिक ज्ञान के साथ–साथ आध्यात्मिक ज्ञान से लैस करना और उसे आत्म–प्राप्ति के लिए प्रेरित करना था। मध्ययुगीन युग में, शिक्षक का कार्य अपने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना था। लेकिन इक्कीसवीं सदी के एक शिक्षक को 'ज्ञान के व्याख्याकार' के रूप में कार्य करना पड़ता है। शिक्षक की भूमिका और कार्य में परिवर्तन के अनुरूप, शिक्षक शिक्षा का पैटर्न भी समय–समय पर विविध होता है। प्राचीन भारत में, शिक्षा मुख्य रूप से वेदों (ऋग, यगुर, साम और अथर्व) और वेदांगों (शिक्षा, छंदों, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतशा) पर केंद्रित थी। 'गुरुकुल 'प्रणाली उस समय प्रचलित थी जिसमें गुरु–शिक्षक और' शिष्य–शिष्य के बीच एक अंतरंग संबंध था, और instruction शिक्षा का व्यक्तिगतकरण 'प्रणाली की एक मुख्य विशेषता थी। शिक्षक का कर्तव्य केवल विद्यार्थियों को पढ़ाना ही नहीं था, बल्कि वास्तविक जीवन में जो सिखाया जाता है, उसका अभ्यास करना भी था। वैदिक काल में ज्ञान मौखिक रूप से प्रसारित होता था। छात्रों ने शिक्षक से मौखिक रूप से दोहराए गए पाठों को याद किया। चूंकि 'संदर्भ' का कोई अन्य तरीका संभव नहीं था, इसलिए शिक्षक ज्ञान का कोष बना रहा। शिक्षकों द्वारा शिष्यों को ज्ञान हस्तांतरित करने के लिए विभिन्न तरीकों को नियोजित किया गया था। प्रकृति और कहानियों के दृष्टांतों का उपयोग दार्शनिक अवधारणाओं की खोज के लिए किया गया था। गुरुओं के इन तरीकों को शिष्यों ने अपनाया और अगली पीढ़ी के शिक्षकों को हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार नकल और पुनरावृत्ति के माध्यम से शिक्षण के तरीकों के प्रसारण ने शिक्षकों में विद्वानों के परिवर्तन की सुविधा प्रदान की। वरिष्ठ विद्यार्थियों को शिक्षकों की स्थिति में शामिल करने की निगरानी प्रणाली को प्राचीन शैक्षिक प्रणाली (डैश, 2004) के योगदान के रूप में माना जा सकता है।

२ बौद्ध काल:

इस स्तर पर शिक्षकों की भूमिकाओं में बदलाव हुआ। विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में ज्ञान के विकास ने शिक्षकों को ज्ञान की विशेष शाखाओं में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक किया। पाठ्यक्रम में केवल धार्मिक अध्ययन ही नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष विषय भी शामिल थे। बौद्ध काल में नालंदा और तक्षशिला जैसी उच्च शिक्षा के केंद्र थे। शिक्षकों ने मौखिक प्रक्रिया के अलावा विभिन्न तरीकों जैसे चर्चा, बहस, सवाल–जवाब, प्रदर्शनी आदि को नियोजित किया और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया। शिक्षक की तैयारी के लिए औपचारिक कार्यक्रमों की अनुपस्थिति में, शिक्षकों की नकल के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले शिक्षण के तरीकों में विषय वस्तु और कौशल की महारत शिक्षक बनने के तरीके थे।

३ मध्ययुगीन काल:

मध्यकाल के दौरान मुस्लिम शासकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई थी। मोहम्मद गोरी ने इस्लामिक सिद्धांतों और संस्कृति को फैलाने के इरादे से मकतब नामक कई प्राथमिक स्कूलों की शुरुआत की। उस समय मदरसा उच्च शिक्षा संस्थान थे। प्रारंभिक चरणों में तीन आर–रीडिंग, राइटिंग और अंकगणित में महत्व दिया गया था। कुरान का अध्ययन अनिवार्य था। व्याकरण, अंकगणित, तर्कशास्त्र, विज्ञान और दर्शन उच्च चरणों में पढ़ाए जाते थे। मध्ययुगीन काल में रॉट द्वारा सीखने को प्रोत्साहित किया गया था। कुरान से छंदों को समूह–ड्रिल विधि द्वारा सिखाया गया था। उच्च चरणों में शिक्षा में कुछ प्रकार की बहस और चर्चाएँ कार्यरत थीं। इस अवधि में भी शिक्षक तैयार करने की विधि ज्यादातर पुराने शिक्षकों ने अभ्यास करने की नकल की थी। अच्छे और अनुभवी शिक्षकों ने प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी अनुपस्थिति में जूनियर छात्रों को देखने और पढ़ाने के लिए ट्यूटर के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार मध्यकाल में भी भावी शिक्षकों की तैयारी के लिए निगरानी प्रणाली प्रचलित थी।

४ पश्चिमी शक्ति के तहत विकास:

एक नई प्रकार की शैक्षिक प्रणाली, जो मौजूदा स्वदेशी प्रणाली से काफी अलग है, भारत में पश्चिमी शक्तियों के आगमन के साथ स्थापित हुई। यूरोपीय मिशनरियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजी शिक्षा के लिए कई स्कूल शुरू किए जिनमें देशी बच्चों को भी भर्ती किया गया था। स्कूलों में अधिक से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता ने 'निगरानी प्रणाली' से आगे बढ़कर शिक्षकों के व्यवस्थित प्रशिक्षण की शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 1802 में प्रारंभिक विलियम केरी ने सेरामपुर में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक सामान्य स्कूल की स्थापना की। विभिन्न समाजों ने भी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रयास किए। 1819 में स्थापित कलकत्ता स्कूल सोसाइटी ने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरुआती कदम उठाए। बाद में, शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता ने मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने 10 मार्च, 1826 के अपने मिनट में देखा (जैसा कि सेखर, 2001, .22 में उद्धृत है) ''बेहतर शिक्षा प्राप्त शिक्षकों के निकाय के बिना शिक्षा में कोई प्रगति नहीं की जा सकती है''। उन्होंने शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए और सिफारिशें कीं। माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की तैयारी के लिए मद्रास में सरकार के तहत 1826 में एक सामान्य स्कूल की स्थापना की गई थी। बाद में यह नॉर्मल स्कूल प्रेसीडेंसी कॉलेज में विकसित हुआ। 1828 में, कलकत्ता लेडीज सोसाइटी ने महिला शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित कीं। बॉम्बे की नेटिव एजुकेशन सोसायटी ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण वर्ग शुरू किया। 1849 में बंबई में 1847 में कलकत्ता और 1850 और 1857 के बीच आगरा, मेरठ और बनारस में सामान्य स्कूल शुरू किए गए। 1854 में वुड्स डिस्पैच ने ब्रिटिश भारत की शैक्षिक नीति में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। शिक्षा को सरकार की जिम्मेदारी माना गया। इस दस्तावेज की सिफारिशों ने संगठित शिक्षा प्रशासन, जन शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत की। वुड्स डिस्पैच ने भारत के हर प्रांत में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण स्कूल शुरू करने की सिफारिश की। 1856 में मद्रास में गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल शुरू किया गया था। हंटर कमीशन 1882, ने सामान्य स्कूलों की स्थापना की सिफारिश की, चाहे सरकारी हो या निजी सभी प्राथमिक स्कूलों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इस आयोग ने किसी भी माध्यमिक विद्यालयों में एक शिक्षक के रूप में स्थायी रोजगार के लिए शिक्षण के सिद्धांतों और अभ्यास में परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सिफारिश की। स्नातकों के लिए, यह दूसरों की तुलना में प्रशिक्षण के एक छोटे पाठ्यक्रम का सुझाव दिया। हंटर आयोग की सिफारिशें नए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और 1892 तक चलींय पुरुषों के लिए 116 और महिलाओं के लिए 15 प्रशिक्षण संस्थान थे। मद्रास नॉर्मल स्कूल को 1886 में एक कॉलेज का दर्जा दिया गया था और यह मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था। देश के विभिन्न हिस्सों में L- T- (लाइसेंसिंग इन टीचिंग) और B- T- (बैचलर इन टीचिंग) पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले प्रशिक्षण कॉलेजों की शुरुआत की गई। 1917 के सैडलर कमीशन ने देखा कि शिक्षक शिक्षा के तीन आवश्यक घटक – विषय वस्तु का ज्ञान, व्यावहारिक प्रशिक्षण और सैद्धांतिक प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ था। इसने बी.ए. में एक वैकल्पिक विषय के रूप में शिक्षा शुरू करने की सिफारिश की। स्तर, और शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री की शुरूआत। सैडलर आयोग की सिफारिशों ने भारत में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुधार में मदद की। हार्टोग समिति 1929 ने पाया कि केवल 44: प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था और केवल 28: ने ही मध्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यह सुझाव दिया गया कि प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के मानक में सुधार किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण स्कूलों को बेहतर सुविधाएं और उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। सैडलर आयोग की सिफारिशों के बाद, अधिकांश विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के संकायों की स्थापना की। आंध्र विश्वविद्यालय ने बी.एड. 1932 में डिग्री और बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने स्नातकोत्तर उपाधि, एम.एड. 1936 में। 1941 में, 612 सामान्य स्कूल थे, जिनमें से 376 पुरुषों के लिए और 236 महिलाओं के लिए थे। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) ने 1994 में शिक्षा की एक योजना ''पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया'' प्रस्तुत की, जिसे ''सरजेंट प्लान'' के नाम से जाना जाता है। इसने देश में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए। इस बीच भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों ने अपना आकार प्राप्त कर लिया और कम से कम पाठ्यक्रम के संगठन में अलग–अलग प्रांतों में लगभग समान हो गए: सिद्धांत और व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों का

समावेश। मैट्रिक के बाद दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आमतौर पर प्राथमिक शिक्षकों की तैयारी के लिए स्वीकार किया जाता है जबकि स्नातक शिक्षकों के लिए एक वर्षीय पाठ्यक्रम।

५ आजादी के बाद शिक्षक शिक्षा:

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत ने विकास के एक नए चरण में प्रवेश किया। बदली हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में शिक्षा की प्रणाली के साथ–साथ शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने शैक्षिक परिदृश्य को सुधारने के इरादे से अच्छी संख्या में समितियों और आयोगों की नियुक्ति की।

राष्ट्रीय आयोग और समितियाँ :

- विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948 – 49): विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, डॉ एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित किया गया था, स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के सुधार के लिए किया गया था। आयोग ने देखा कि भले ही विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में पेश किए गए सिद्धांत पाठ्यक्रमों में कोई अंतर नहीं था, लेकिन पालन किए जाने वाले प्रथाओं में बहुत अंतर था, और स्कूल अभ्यासों के लिए अधिक समय देने और अभ्यास करने के लिए अधिक वजन देने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को फिर से तैयार करने की सिफारिश की गई थी। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करना।
- माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952 – 53): डॉ। ए। लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने मुक्त भारत के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत किया। इसने शिक्षण के लिए गतिशील तरीकों की सिफारिश की और सुझाव दिया कि शिक्षण को 'गतिविधि पद्धति' और 'परियोजना पद्धति' के माध्यम से मौखिक और मेमोराइजेशन से शिक्षण में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। आयोग ने शिक्षक तैयारी के लिए भी विशेष दिशानिर्देश बनाए।
- शिक्षा आयोग (1964–66): एक प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद् डॉ। डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग ने ग्यारह भारतीय सदस्यों और पांच अन्य लोगों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय रचना की थी।
- शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1968): शिक्षा आयोग (1964 – 66) की सिफारिशों को शामिल करते हुए, भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1968) की घोषणा की गई थी। नीति ने शिक्षकों की सेवा शर्तों, शिक्षकों की शैक्षणिक स्वतंत्रता और सेवा शिक्षा में सिफारिशें कीं।
- राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983 – 85): भारत सरकार द्वारा 1983 में प्रो। डी। पी। की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया यह आयोग। चट्टोपाध्याय, ने शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार के लिए कई सिफारिशें कीं। शिक्षण पेशे के लिए प्रशिक्षुओं के चयन के बारे में, आयोग ने सुझाव दिया कि (राव, 1998 में उद्धृत) ''निम्नलिखित कारकों पर ध्यान दिया जा सकता है:

➢ 'अच्छी कायाय
➢ 'भाषाई क्षमता और संचार कौशलय
➢ 'सामान्य मानसिक क्षमता की एक उचित डिग्री।
➢ 'दुनिया की सामान्य जागरूकताय
➢ 'जीवन पर एक सकारात्मक दृष्टिकोणय तथा
➢ 'अच्छे मानवीय संबंधों की क्षमता ''

आयोग ने आगे सिफारिश की कि प्रशिक्षुओं का चयन उद्देश्य परीक्षण, रेटिंग स्केल, समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के संयोजन के माध्यम से किया जाना चाहिए। आयोग ने शिक्षा के एक शैक्षिक के रूप में (1) अध्ययन के साथ व्यावसायिक तैयारी का भी सुझाव दिया, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा का समाजशास्त्र और शैक्षिक दर्शन, (2) अभ्यास शिक्षण और इसकी सामग्री–सह–पद्धति, और (3) विभिन्न प्रकार के कौशल सीखना। एक शिक्षक की भूमिका से संबंधितय शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर तैयार करना शामिल है।

- शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986): भारत सरकार ने 1985 में एक नई शैक्षिक नीति की घोषणा की। तदनुसार शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में बनाई गई थी। इसने अध्यापक शिक्षा पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं।

1. वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों के बीच नया ज्ञान, कौशल और अनुकूल दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए।

2. शिक्षकों का उन्मुखीकरण शिक्षक शिक्षा की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए।

3. राज्य स्तर पर एससीईआरटी की तरह, जिला स्तर की संस्था स्थापित की जा सकती है और इसे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) (शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986) कहा जा सकता है।

विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, देश में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में कई प्रगतिशील परिवर्तन हुए। इसके अलावा, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को संतुलित तरीके से विकसित करके सतत आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। शिक्षा को अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्रों में से एक के रूप में माना जाता था और सभी पंचवर्षीय योजनाओं में इसे महत्व दिया जाता था। परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा सामान्य रूप से शिक्षा प्रणाली में सुधार और विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

६ निष्कर्ष:

शिक्षण एक अत्यधिक पेशेवर गतिविधि है जो विशेष ज्ञान, कौशल और व्यवहार की मांग करती है। शिक्षक व्यावसायिकता में क्षमता, प्रदर्शन और व्यवहार शामिल है जो स्कूल और समाज में शिक्षक के व्यक्तित्व पर प्रतिबिंबित करता है। व्यावसायिक दक्षता शिक्षण पेशे में मौलिक है जिसमें कक्षा प्रक्रियाओं के लिए शिक्षक की तैयारी, विषय का ज्ञान प्राप्त करना और बच्चों के व्यक्तित्व विकास की सुविधा शामिल है। एक प्रभावी शिक्षक की दक्षताओं में पारस्परिक संचार, शैक्षणिक सशक्तिकरण और संगठनात्मक नेतृत्व शामिल हैं। बच्चों के समग्र विकास के संदर्भ में शिक्षक के प्रदर्शन में व्यावसायिक क्षमता होती है। सक्षम शिक्षक को बच्चों और समाज के हित में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। इस पर उपयुक्त टिप्पणी की गई है, ''यदि आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं लेकिन यदि आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं, तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं और यदि आप एक शिक्षक को शिक्षित करते हैं, तो आप पूरे समुदाय को शिक्षित करते हैं''। वर्तमान में शिक्षक सूचना के मात्र प्रसारणकर्ता नहीं हैं, बल्कि छात्रों के मार्ग में सहायक अधिक ज्ञान के लिए आग्रह करते हैं।

संदर्भ:

1. अग्रवाल जे.सी. एक विकासशील समाज में शिक्षक और शिक्षा। नई दिल्लीः विकास, 1996।
2. भारत में बलवरिया आर, गुप्ता पी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षक शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक ई–जर्नल। 2014; 3 (1): 54–65।
3. डॉ। सचदेवा एम.एस. भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा के लिए एक नया दृष्टिकोण। लुधिनाः विनोद प्रकाशन, 1996।
4. सरकार। भारत की। शिक्षा आयोग (1964–66)। नई दिल्लीः सरकार। भारत की। सरकार। भारत की। (1986)। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति – 1986. नई दिल्लीः एमएचआरडी, 1966।
5. मानव संसाधन विभाग मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई दिल्ली, 1980।
6. कपिल, एच.के. (2001) : ''अनुसंधान विधियॉ, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
7. मंगल, एस.के. (2006) : ''शिक्षा मनोविज्ञान'', प्रिन्ट्स हॉल ऑफ प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।